



Neutral Citation No. - 2026:AHC:54980

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 9280 वर्ष 2026

शिवम कुमार

...आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

...विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : कृष्ण दत्त अवस्थी

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 67

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्ण दत्त अवस्थी और राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री कुंवर तेजेंद्र बहादुर को सुना गया।
2. वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक को थाना औरैया, जिला औरैया में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 239 वर्ष 2025, धारा 85, 80 बी.एन.एस. और धारा 3/4 दहेज निषेध अधिनियम के अंतर्गत विचारण लंबित रहने के दौरान जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि यद्यपि आवेदक मृतका का पति है, लेकिन झूठे आरोपों के आधार पर उसे वर्तमान मामले में फंसाया गया है।
4. उन्होंने आगे तर्क दिया कि वास्तव में शादी के बाद मृतका गर्भधारण नहीं कर पा रही थी और जब यह पता चला कि उसका गर्भाशय ही नहीं है, तो वह गहरे अवसाद में चली गई और इसी कारण से उसने अपनी शादी के ठीक एक साल बाद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उन्होंने आगे बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी संकेत देती है कि उसकी मृत्यु फांसी के कारण

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



हुई है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह भी प्रतिबिंबित होता है कि मृतका का गर्भाशय नहीं था। आवेदक का कोई अन्य आपराधिक इतिहास नहीं है और वर्तमान मामले में वह 23.03.2025 से यानी पिछले लगभग एक साल से जेल में है।

5. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, लेकिन आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक तर्कों का खंडन नहीं कर सके।

6. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना और मामले के अभिलेख का परिशीलन किया है।

7. यद्यपि आवेदक मृतका का पति है और उसकी पत्नी की मृत्यु शादी के ठीक एक साल बाद ससुराल में असामान्य परिस्थितियों में हुई है और चार पहिया वाहन की मांग के संबंध में प्रताड़ना का भी आरोप है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट संकेत देती है कि उसकी मृत्यु फांसी के कारण हुई है और इसलिए इस चरण में मृतका द्वारा आत्महत्या किए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है और इस तथ्य को देखते हुए कि उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी गर्भाशय की अनुपस्थिति का संकेत देती है, बहस के दौरान आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताए गए आत्महत्या के कारण को भी इस स्तर पर पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता है।

8. इसके अतिरिक्त, आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वर्तमान मामले में वह 23.03.2025 से यानी पिछले लगभग एक साल से जेल में है।

9. इसके अलावा, कानून स्थापित है कि जब तक दोषी साबित न हो जाए, एक अभियुक्त को निर्दोष माना जाता है और जमानत आवेदन को दंडात्मक या निवारक उद्देश्य के लिए खारिज नहीं किया जाना चाहिए।

10. इसलिए, ऊपर चर्चा किए गए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मेरी राय में आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

11. तदनुसार, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, वर्तमान जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



12. आवेदक- **शिवम कुमार** को उपर्युक्त मामले में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि की दो जमानतें प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) आवेदक नियत तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा, जब तक कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न मिल जाए।

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को बताने से विमुख हो या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ न करे।

(iii) आवेदक किसी भी आपराधिक और असामाजिक गतिविधि में लिप्त नहीं होगा।

13. उपरोक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अभियोजन पक्ष आवेदक की जमानत रद्द करने के लिए इस न्यायालय के समक्ष आवेदन करने के लिए स्वतंत्र होगा।

14. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहाँ की गई टिप्पणियाँ केवल जमानत आवेदन के निस्तारण से संबंधित पक्षों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तक सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का विचारण के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन)

18 मार्च, 2026

शाहरोज

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।